ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

It Was Money All The Time...

Trump warned, "I will be watching this inexperienced Communist. If he starts implementing his Communist ideas, opposes ICE raids (for illegal immigrants), I will send the Federal forces (US Army) into the city. I will cut Federal funding for New York, have a look at his immigration details, and maybe deport him!"

The Slave Fed Democracy

The Hidden Hands Behind the White House: The Laborers Who Built an American Symbol

'उन्नीस सौ सैंतीस में राष्ट्रीय गान के चार छंद हटवाकर पं. नेहरू ने देश के विभाजन का बीज बोया था'

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय गान वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगाँठ पर आयोजित समारोह में सार्वजनिक मंच से पं. नेहरू पर यह आरोप लगाया

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 नवम्बर। बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले, जिसमें मुस्लिम बहुल सीमांचल जिले शामिल हैं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने "वंदे मातरम्" विवाद को दोबारा छेड़ दिया है। उन्होंने 1937 में इस गीत से कुछ महत्वपूर्ण स्टैन्ज़ा हटाने के लिये, कांग्रेस, और विशेष रूप से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, की कड़ी आलोचना की है।

योगी आदित्यनाथ और गिरिराज सिंह जैसे कुछ नेताओं की इक्का-दुक्का टिप्पणियों को छोड़ दें, तो इस बार के बिहार चुनाव में भाजपा ने हिंदुत्व का मुद्दा नहीं उठाया है। चुनाव में बेरोजगारी, पलायन और विकास की कमी जैसे मुद्दे छाए रहे हैं। लेकिन मोदी ने वंदे मातरम् के मुद्दे को उठाकर हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश की है।

- मोदी ने इस अवसर पर राष्ट्रीय गान के छंदों को पढ़कर सुनाया और कहा, कांग्रेस ने केवल प्रथम दो छंदों को स्वीकार करके राष्ट्रीय गान का स्वरूप दिया और चार छंद इतिहास में दफन हो गए।
- इस संदर्भ में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सी.आर. केशवन ने 1937 का वह पत्र भी पेश किया जो नेहरू ने सुभाष चन्द्र बोस को लिखा था।
- उस पत्र में नेहरू जी ने लिखा था कि बाकी छंदों से मुसलमानों को आपत्ति हो सकती है।
- जैसा कि विदित ही है, चार छंदों में देश को दुर्गा, लक्ष्मी व सरस्वती का स्वरूप बताया गया है।
- केशवन के अनुसार, नेहरू जी के विचार एक ऐतिहासिक भूल थी, क्योंकि इससे देशभक्ति पूर्ण गान का राष्ट्रीय प्रतीक कमज़ोर हुआ।
- यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अब तक के बिहार के चुनाव प्रचार में भाजपा ने हिन्दुत्व को केवल पृष्ठभूमि में ही रखा था। पर, दूसरे चरण में सीमांचल जिलों में मतदान होगा, जो मुस्लिम प्रभाव की सीटें हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या सीमांचल क्षेत्र में मतदान से पूर्व वंदे मातरम् को विवाद के रूप में प्रस्तुत करके भाजपा अपना हिंदू वोट बैंक पक्का कर रही है।

राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ के वर्षभर चलने वाले उत्सव का उद्घाटन करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने गीत के अहम पदों को हटाकर विभाजन के बीज बोए थे। इस अवसर पर, उन्होंने पूरे गीत का पाठ भी किया।

छह पदों के इस गीत ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनता को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन इसके केवल पहले दो पदों को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पूर्व विधायक मलिंगा के खिलाफ सुनवाई जयपुर में ही होगी

जयपुर, 7 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली कंपनी के एईएन से मारपीट के मामले में पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा के खिलाफ धौलपुर की अदालत में चल रही सुनवाई को जयपुर की एससी, एसटी कोर्ट में ट्रांसफर करने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर अपील को भी खारिज कर दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश गिर्राज सिंह मलिंगा की अपील

- सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के केस जयपुर ट्रॉंसफर करने के निर्णय को बरकरार रखा।

को खारिज करते हुए दिए। अपील में राजस्थान हाईकोर्ट के गत जुलाई माह के आदेश को चुनौती दी गई थी।

अपील में कहा गया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने केस को गलत तरीके से दूसरे जिले में ट्रांसफर किया है। इसके अलावा शिकायतकर्ता के परिजन वकील हैं और जयपुर में प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे में वे सुनवाई में व्यवधान डालते हैं। इसलिए मामले को वापस धौलपुर या भरतपुर कोर्ट में शिफ्ट किया जाए। पीड़ित हर्षाधिपति की ओर से कहा गया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'छठ पूजा के अवसर पर घर लौटे बिहारी चुनाव का अबूझ रहस्यमय पहलू हैं'

ये प्रवासी बिहारी मतदान तक वापस नहीं लौटे और उन्होंने जमकर वोटिंग की, ऐसा प्रशांत किशोर का मानना है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 नवम्बर। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को कहा कि छठ पर्व के लिए बिहार लौटे वे प्रवासी, जो अब तक अपने काम की जगहों पर वापस नहीं गए हैं, विधानसभा चुनावों में "एक्स फैक्टर" साबित हो सकते हैं।

पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार, जिनकी नई पार्टी को, विभिन्न सर्वेक्षणों और जनमत संग्रहों के अनुसार, "प्रवासियों" के बीच काफी समर्थन मिल रहा है, ने यह दावा पहले चरण के मतदान के बाद किया, जिसमें रिकॉर्ड 64.66 प्रतिशत मतदान हुआ।

किशोर ने कहा, "स्वतंत्रता के बाद से अब तक का सबसे अधिक मतदान यही साबित करता है कि बिहार में बदलाव की बहुत ही जबरदस्त इच्छा है। यहाँ के लोग लगभग 30 साल से एक राजनीतिक जड़ता में फंसे हुए हैं।"

उन्होंने कहा कि अब लोगों को एक नई उम्मीद की झलक दिख रही है, क्योंकि उनकी एक साल पुरानी पार्टी एक व्यवहारिक और मजबूत विकल्प के रूप में उभरी है।

- प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि मतदान प्रतिशत में जो ऐतिहासिक वृद्धि हुई है, उसका कारण भी इन्हीं प्रवासियों का वोट है।
- प्रशांत किशोर का यह भी दावा है कि उनकी जन सुराज पार्टी ने इन प्रवासी बिहारियों की सोच पर बहुत प्रभाव डाला है।
- जैसा कि इन बिहारी प्रवासियों के विभिन्न ओपिनियन पोल सर्वे से स्पष्ट नज़र आया।
- प्रशांत किशोर ने यह भी पुरजोर ढंग से कहा कि बिहारियों में परिवर्तन की भारी और गहरी चाहत है और वे गत तीस साल से राजनीतिक दलदल में फंस गए थे और निकलने क लिए छटपटा रहे थे।
- अब उनकी पार्टी एक राजनीति विकल्प के रूप में सामने आई है और बिहारियों में आशा की किरण जगी है। यह भी अभूतपूर्व मतदान का एक कारण है।

साल 2005 से सत्ता में रहे एनडीए की आलोचना करते हुए जन सुराज पार्टी के संस्थापक ने कहा, "इन लोगों को लगा था कि वे महिलाओं को कुछ खैरात और रियायतें देकर चुनाव जीत सकते हैं। हाँ, महिलाएं बड़ी संख्या में वोट देने आईं, लेकिन इस चुनाव में असली "एक्स फैक्टर" प्रवासी ही हैं।"

चीन के युद्ध पोतों की संख्या अमेरिकी नौसैनिक पोतों से 20 प्रतिशत ज्यादा हो चुकी है

और हाल ही में चीन ने अपने नवीनतम एयरक्राफ्ट कैरियर "फुजियान" को नौसेना में शामिल किया, जो तकनीकी दृष्टि से भी कमज़ोर नहीं है और उसके नौसैनिक जहाज अमेरिका के नौसैनिक जहाजों से आगे निकल रहे हैं

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 नवम्बर। चीन ने इस सप्ताह अपने नवीनतम विमानवाहक पोत "फुजियान" को नौसेना में शामिल कर लिया, जिससे यह बात एक बार फिर साबित हो गई है कि जहाजों की संख्या के लिहाज़ से चीन अब दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री नौसेना है।

फुजियान विमानवाहक पोत आकार और क्षमता दोनों में अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े पोतों के बराबर है। इसे पूरी तरह चीन में ही एक घरेलू शिपयार्ड में तैयार किया गया है। इसमें एक विशेष विमान लिफ्ट प्रणाली (एयरक्राफ्ट लिफ्ट सिस्टम) लगाई गई है, जो इसके विमानों को हथियारों और ईंधन के अधिक भार के साथ आसानी से उड़ान भरने में सक्षम बनाती है।

''इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट'' नामक यह विशेष विमान

- यह स्थिति अमेरिका के लिए चुनौतीपूर्ण तो है ही, पर, भारत के लिए भी चिंता का विषय है।
- चीन के नौसैनिक जहाज हिंद महासागर में आए दिन अतिक्रमण और घुसपैठ करते रहे हैं और कभी भी आमने-सामने की स्थिति बन सकती है।
- वैसे भी चीन साउथ चाइना सी को अपना प्ले ग्राउण्ड मानता रहा है।
- फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम, चीन की इस दादागिरी से काफी त्रसित हैं। पर, विरोध करने की स्थिति में नहीं हैं, लगभग ऐसी ही स्थिति भारत की हिंद महासागर के संदर्भ में है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजकॉम्प में करोड़ों के फर्जीवाड़े पर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा

जयपुर, 7 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजकॉम्प के लीगल मेट्रोलॉजी एवं ईपीडीएस प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े के मामले में कार्मिक सचिव, आईटी सचिव और एसीबी डीजी से जवाब मांगा है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश

- अदालत ने कार्मिक सचिव, आईटी सचिव तथा एसीबी डीजी से जवाब तलब किया है।

पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता पीसी भंडारी ने अदालत को बताया कि राजकॉम्प के लीगल मेट्रोलॉजी एंड ईपीडीएस प्रोजेक्ट में दो लोगों को साल 2020 तक करीब तीन लाख रुपए प्रतिमाह के आधार पर नियुक्त किया गया। जिसे बार-बार कांट छांट कर 2022 तक बढ़ा या गया। इसी तरह ईपीडीएस प्रोजेक्ट में पोस मशीन की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अधिकतर देश के इकॉनमिस्ट एसबीआई के अध्यक्ष शेट्टी के आंकलन से सहमत हैं

शेट्टी का मानना है कि आंकड़ों की दृष्टि से भारत की जीडीपी आदि का मापदंड कुछ ज्यादा ही आशाजनक तस्वीर पेश करते हैं

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 नवंबर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की दूसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा के बाद बोलते हुए चेयरमैन सी.एस. शेट्टी ने भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर सतर्क आशावाद जताया। उन्होंने एक ऐसे देश की तस्वीर पेश की, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी लचीला और मजबूत बना हुआ है। लेकिन इस आत्मविश्वास के पीछे एक जटिल सच्चाई भी छिपी है, जो यह संकेत देती है कि भारत की वृद्धि भले ही मजबूत दिख रही हो, पर वह अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, वर्ष 2025 में ग्लोबल जीडीपी वृद्धि लगभग 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके मुकाबले, भारत की जीडीपी के वित्त वर्ष 2025-26 में 6.8 प्रतिशत और 2026-27 में 6.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। शेट्टी ने इसका श्रेय मजबूत निवेश, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार और बढ़ती खपत को दिया। आंकड़े उत्साहजनक हैं, लेकिन कुछ विश्लेषक चेतावनी देते हैं कि इनके पीछे कई गहरी कमजोरियां छिपी हैं, जैसे कि ऋण और जमा राशि की वृद्धि में बढ़ता अंतर, लगातार बनी हुई महंगाई और अलग-अलग क्षेत्रों में असमान सुधार।

शेट्टी ने बताया कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ऋण वृद्धि 11.5 प्रतिशत है, जबकि जमा वृद्धि केवल 9.5 प्रतिशत पर अटकी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले वित्त वर्ष में दोनों 11 से 12 प्रतिशत के आसपास स्थिर हो जाएंगे। हालांकि, यह आशावाद अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है। लेकिन अर्थशास्त्री आगाह करते हैं कि जमा वृद्धि में धीमी वृद्धि परिवारों की कमजोर वित्तीय स्थिति और घटती बचत को दिखाती है, क्योंकि बढ़ती महंगाई से लोगों की वास्तविक आय घट रही है। अगर यह स्थिति जारी रही, तो बैंकों के लिए कर्ज देने की क्षमता सीमित हो जाएगी, जिससे उन्हें थोक उधारी या ऊंची ब्याज दरों पर निर्भर होना पड़ेगा, जो उनके मुनाफे पर दबाव डालेगा।

- इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार, भारत की इकॉनमी की हालत ठीक तो है, पर, सिस्टम में काफी आंतरिक कमज़ोरियाँ भी हैं, जिनसे सावधान रहना जरूरी है।

नोमुरा की मुख्य अर्थशास्त्री सोनल वर्मा के अनुसार, "लोग अब अपनी बचत का इस्तेमाल रोजमर्रा की खपत के लिए करने लगे हैं। यह दीर्घकालिक वृद्धि का टिकाऊ आधार नहीं है।"

इसके अलावा, घरेलू मांग भले ही कागज़ों पर मजबूत दिख रही हो, पर उसका बड़ा हिस्सा अमीर तबके की खपत से आ रहा है। शहरी इलाकों में गाड़ियों, मकानों और उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद बढ़ी है, लेकिन ग्रामीण खपत, जो असली आर्थिक सुधार का पैमाना मानी जाती है, अब भी कमजोर है। अनियमित मानसून, ठहरी हुई ग्रामीण मजदूरी और कृषि आय में कमी ने ग्रामीण मांग को दबा दिया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र पंत ने कहा, "ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार की बात शायद अभी जल्दबाजी होगी। हम कुछ क्षेत्रों में सुधार

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शराबी डम्पर चालक की पैरवी से वकीलों का इन्कार

जयपुर, 7 नवंबर। हरमाड़ा थाना इलाके में शराब के नशे में धुत्त होकर 14 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले डंपर चालक कल्याण मीणा को चौमूं के अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। जहां

- शराब के नशे में धुत्त डम्पर चालक ने 14 लोगों को कुचल दिया था।

से न्यायालय ने उसे 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। इस भीषण हादसे को देखते हुए वकीलों ने डंपर चालक कल्याण मीणा की पैरवी करने से इंकार कर दिया। न्यायालय ने आरोपी कल्याण मीणा को पेश करने के साथ ही पुलिस को इस मामले में गंभीर धाराओं के तहत अनुसंधान करने के आदेश दिए। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान सरकार की ओर से अभियोजन

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

फीफा ट्रंप को शांति पुरुस्कार देने की तैयारी में है

फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फैंटीनो, ट्रंप के नज़दीकी समर्थक हैं और 2026 में फीफा कप के आयोजन के लिए अमेरिका की निविदा के प्रबल समर्थक हैं

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 नवम्बर। जब इस हफ्ते फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो से पूछा गया कि क्या डॉनल्ड ट्रम्प को नया फीफा शांति पुरस्कार मिलेगा, तो उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, 5 दिसंबर को आप देख लेंगे। इस एक वाक्य ने वाशिंगटन डी.सी. में होने वाले विश्व कप ड्रॉ से पहले तरह-तरह के कयासों का तूफान खड़ा कर दिया है, जहां यह पहला पुरस्कार दिया जाएगा।

इसके बाद जो सवाल उठता है, वह यह है कि नोबल शांति पुरस्कार की तुलना में फीफा शांति पुरस्कार की अहमियत क्या होगी।

नोबेल शांति पुरस्कार, जिसे 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने स्थापित किया था, लंबे समय से दुनिया के नैतिक दिशासूचक के रूप में जाना जाता है। नॉर्वेजियन संसद के अधीन एक स्वतंत्र समिति द्वारा संचालित इस पुरस्कार ने नेल्सन मंडेला और मलाला यूसुफ़ज़ई से लेकर संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम तक, कई बार, इतिहास को आकार दिया है। भले ही यह कभी-कभी विवादास्पद रहा हो, जैसे बराक ओबामा को 2009 में या 1994 में यासिर अराफात और राबिन को दिये गये पुरस्कार, लेकिन नोबेल पुरस्कार की साख इसकी स्वतंत्रता और नैतिक उद्देश्य से उपजी है।

इसके विपरीत, फीफा का नया शांति पुरस्कार एक ऐसे खेल संगठन की पहल है, जो अपनी अंतरात्मा की आवाज से ज्यादा अरबों डॉलर की स्पॉन्सरशिप और भ्रष्टाचार घोटालों के लिये जाना जाता है। "फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड" नामक यह पुरस्कार "शांति के लिए असाधारण कार्यों" का सम्मान करने का दावा करता है। लेकिन इसमें न तो नामांकन की कोई स्पष्ट प्रक्रिया है, न ही जूरी की जानकारी सार्वजनिक की गई है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता पूरी तरह फीफा के शब्दों पर टिकी है।

- अतः इन्फैंटिनो द्वारा पाँच दिसम्बर को वॉशिंगटन में निविदाओं पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
- इन्फैंटिनो इस मौके को ट्रंप को उपकारित करने का अच्छा अवसर मानते हैं। फीफा पीस प्राइस दे कर।
- ट्रंप को भी इस "सम्मान" से राजनीतिक लाभ मिलने की अपेक्षा है, क्योंकि वॉशिंगटन के कैनेडी सैंटर में ट्रंप को इस सम्मान से नवाजा जा सकता है।
- पर, अहं सवाल यह है कि फीफा शांति पुरुस्कार की नोबेल पीस प्राइस से तुलना होगी ही और फीफा सम्मान बहुत फीका नज़र आयेगा, नोबल पीस प्राइस के समक्ष।
- नोबल पीस प्राइस 1895 से दिया जा रहा है और वह राजनीति से अपने आप को अछूता रखता है। दूसरी ओर फीफा विवादित स्पॉन्सरशिप व कॉमर्शियल राईट्स से सदा से ग्रसित रहा है।

अगर यह पुरस्कार ट्रम्प को दिया गया, तो इसे एक राजनीति नाटक के रुप में देखा जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प, इन्फेंटिनो के घनिष्ठ सहयोगी रहे हैं और 2026 विश्व कप की संयुक्त मेज़बानी (अमेरिका, कैनडा और मेक्सिको) के प्रबल समर्थक भी रहे हैं। ऐसे में "शांति" के नाम पर दिया गया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आरएएस का बंद लिफाफा खोल परिणाम जारी करें

जयपुर, 7 नवंबर। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह आरएएस हायर सुपर टाइम स्केल में साल 2021-2022 की रिक्ति के विरुद्ध राजस्व मंडल के पूर्व सदस्य

- अपीलीय अधिकरण ने कहा कि ऐसा प्रमोशन एसीबी कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा।

भंवरलाल मेहरडा की पदोन्नति के परिणाम का बंद लिफाफा खोलकर परिणाम जारी करे। यदि वह योग्य पाया जाता है तो उसे उस तिथि से पदोन्नत किया जाए, जिस तिथि से उसके जूनियर अफसरों को प्रमोशन मिला है। अधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यह पदोन्नति एसीबी कोर्ट में लंबित प्रकरण के फैसले के अधीन रहेगी। अधिकरण ने यह आदेश भंवरलाल मेहरडा की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)